जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 30 संख्याः 37 प्रभात अजमेर, शनिवार 6 सितम्बर, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ट्रम्प के ''ट्रेड'' सलाहकार की राय पर अमेरिका ''सर्विस सेक्टर'' पर भी टैरिफ लगायेगा?

इस नए टैरिफ से भारत का आई.टी. सेक्टर ''पंक्चर'' हो जायेगा

- चीन व पूर्वी एशिया के देश मुख्य रुप से सामान निर्यात करते हैं अमेरिका को, पर भारत का निर्यात ''आई.टी. सर्विसेज़'' है, और यह निर्यात अब 250 अरब डॉलर पहुंच गया है और आई.टी. निर्यात की सफलता के कारण ही भारत ने विदेशों में अपनी पहचान बनाई है।
- शायद ''सर्विसेज़'' पर टैरिफ लगाने की योजना शुरु से ही थी ट्रम्प की, अतः पहले परम्परागत सामान पर टैरिफ लगाना, पूर्व निश्चित रणनीति थी और अब द्वितीय चरण में सर्विस सेक्टर को टैरिफ के दायरे में लेने का इरादा है।
- यह दूसरा चरण, पहले चरण से कहीं ज्यादा भारी पड़ेगा भारत के लिये।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 सितम्बर। अगर डॉनल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की बातों को संकेत माना जाए तो अमेरिका की तरफ से भारत को एक और झटका लग सकता है।

नवारो ने दूरस्थ काम करने वाले कर्मचारियों और विदेशी सेवा प्रदाताओं (ऑफ शोर सर्विस प्रोवाइडर्स) पर टैरिफ लगाने का सुझाव दिया है। ऐसा कदम भारत को घातक चोट पहुँचा सकता है, न सिर्फ इसके निर्यात को बल्कि पूरे सेवा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को भी।

पूर्व का टैरिफ वॉर इसकी तुलना में बहुत मामूली लगेगा, क्योंकि ऐसा कदम भारतीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था को गहरी क्षति पहुँचा सकता है। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें चीन भी शामिल है और जो भौतिक वस्तुओं के निर्यात पर आधारित थीं, के विपरीत, भारत की सफलता की कहानी विदेशी कंपनियों और सरकारों को सेवाएँ देने पर आधारित रही है।

भारत को इस खतरे से निपटने के लिए तुरंत नई रणनीति बनानी होगी और इस मोर्चे पर शांति बनाए रखने के लिए शायद एक-दो कदम पीछे हटना पड़े।

अब तक सेवाओं का निर्यात (सर्विसेज़ एक्स्पोर्ट) ट्रंप के टैरिफ वॉर के दायरे से बाहर था और टैरिफ वॉर में केवल भौतिक वस्तुओं का निर्यात शामिल था। अब नवारो की भड़ास सेवाओं के निर्यात को भी कवर करना चाहती है, जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सफलता और पहचान के लिए आधारित रहा है।

भारत की सर्विस इण्डस्ट्री (सेवा क्षेत्र) 250 अरब डॉलर से अधिक तक फैल चुकी है, जिसका बड़ा हिस्सा सेवाओं के निर्यात से आता है, यहाँ तक कि फ़ॉर्च्यून 500 कंपनियाँ भी सेवा निर्यात में शामिल हैं। इनमें कोडिंग, सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग, परामर्श और बैक ऑफिस का काम शामिल है।

ये सेवाएँ लगातार विकसित होती रही हैं और हाल ही में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और अमेरिकी खरीदारों के बीच लेन-देन की सूची में और भी उच्च मूल्य और जटिल सेवाएँ जुड़ी हैं। कई अमेरिकी कंपनियों ने अपने बैक ऑफिस और ''ग्लोबल केपबिलिटी सेंटर्स'' भारत में स्थापित किए हैं। ये केंद्र भविष्य की परियोजनाओं और अत्याधुनिक क्षेत्रों पर काम करने वाली इन कंपनियों के ब्रेन हैं।

नवारो और उनके जैसे लोग सुझाव दे रहे हैं कि नए कर तंत्रों के माध्यम से इन कर्मचारियों पर टैक्स लगाया जाए, भले ही वे दूरस्थ टैक्स क्षेत्राधिकार में हों। उनकी एम्प्लॉयर कंपनियों से, विदेशी केंद्रों से मिलने वाले काम पर टैरिफ (शुल्क) लिया जा सकता है।

ऐसे विचार शायद शुल्क अभियान की शुरुआत से ही दिमाग में रहे होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

18 माह की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी फूफा को आजीवन कारावास

जयपुर, 5 सितंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आठ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है। पीठासीन

- पॉक्सो मामलों की विशेष जज मीना अवस्थी ने कहा, अभियुक्त ने सगा फूफा होकर रिश्तों की गरिमा को तार-तार किया है, उसने दानव की तरह पैशाचिक कृत्य किया है।

अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सगा फूफा होते हुए 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म कर रिश्ते की गरिमा और विश्वास को तार-तार किया है। उसने दानव की तरह पैशाचिक कृत्य किया है। इस दौरान पीड़िता को कितना दर्द हुआ होगा, यह कल्पना से परे है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यू ट्यूब पर बैन लगाया

नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, इनमें फेसबुक, यू ट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स शामिल हैं

- सरकार की ओर से प्रतिबंध का कारण इन साइट्स द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करना बताया गया है।
- नेपाल के दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और कहा कि ये सभी सोशल मीडिया साइट्स तब तक ''इनएक्टिव'' रहेंगी जब तक वे रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेती।
- सरकार के बार-बार आग्रह पर भी इन साइट्स ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 28 अगस्त को 7 दिन की डैडलाइन दी गई जो बुधवार रात खत्म हो गई। इसके बाद सरकार ने प्रतिबंध लगाने का कठोर कदम उठाया।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 सितम्बर। नेपाल की के. पी. शर्मा ओली सरकार ने गुरुवार (4 सितंबर, 2025) को फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूबय समेत, कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार ने इन कंपनियों पर नेपाल में पंजीकरण की अनिवार्यता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया।

सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उसने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को सभी गैर-पंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स को तब तक निष्क्रिय करने का आदेश दिया है, जब तक वे पंजीकरण नहीं करा लेतीं।

सरकार ने बार-बार के अनुरोधों के बाद 28 अगस्त को सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 7 दिनों की अंतिम समयसीमा दी थी, जो बुधवार रात को समाप्त हो गई।

बुधवार दोपहर को मंत्रालय के प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर ने कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि सोशल मीडिया कंपनियां समयसीमा खत्म होने (अर्द्धरात्रि) से पहले संपर्क करेंगी। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करतीं, तो सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

चूंकि कोई भी कंपनी आगे नहीं आई, इसलिए गुरुवार को मंत्रालय में हुई बैठक में प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया गया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारों ने इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कदम नियमन (रेग्यूलेशन) से अधिक असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश है।

उनका मानना है कि सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तें, जिनमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूरोप के 26 देश यूक्रेन के पक्ष में एकजुट, पर ट्रंप के रुख पर संदेह

इन 26 देशों ने रूस के हमले को रोकने के लिए यूक्रेन में सेना तैनात करने पर भी सहमति दी

- पेरिस में हुए एक शिखर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह जानकारी दी। यह बैठक यूक्रेन में युद्ध रोकने की यूरोपियन कूटनीतिक पहल का अंग थी।
- मीटिंग में अधिकांश देश वीडियो कॉन्फ्रैंस के जरिए शामिल हुए थे। ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ भी मीटिंग में शामिल हुए । बताया जाता है कि ट्रंप ने मीटिंग के दौरान कॉल किया था।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 सितंबर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को कहा कि 26 देशों ने यूक्रेन में भविष्य के किसी भी शांति समझौते को सुनिश्चित करने का वादा औपचारिक रुप से किया है, जिसमें रूसी आक्रामकता को रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती भी शामिल है।

मैक्रों ने पेरिस में हुए एक शिखर सम्मेलन के बाद यह बात कही, जिसमें 30 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल हुए थे, जिनमें से कई वीडियो लिंक के ज़रिए जुड़े थे, लेकिन इस बात का ज्यादा विवरण सामने नहीं आया कि यूरोपीय देश किस तरह से मदद करेंगे या फिर अमेरिका की भागीदारी क्या होगी।

यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप को इस योजना के लिये अमेरिका का पूरा समर्थन देने को राजी करने के लिए यूरोपीय देशों की नवीनतम कूटनीतिक कोशिश थी। ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ इसमें शामिल हुए और वाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि ट्रंप ने बैठक में फोन पर बात की।

मैक्रों ने कहा कि अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पडेगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा। लेकिन ट्रंप पहले भी प्रतिबंधों की धमकी दे चुके हैं, जिन पर अमल नहीं हुआ।

बैठक के दौरान, ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा कि वे रूसी तेल न खरीदें और चीन पर और दबाव डालें, क्योंकि वह रूस के युद्ध को धन मुहैया करा रहा है।

अब तक केवल फ्रांस, ब्रिटेन और एस्तोनिया ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि वे युद्ध के बाद के यूक्रेन में सैनिक भेज सकते हैं। अधिकांश यूरोपीय देश इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर नाटो सैनिकों पर हमला हुआ तो वॉशिंगटन वास्तव में सैन्य रुप से उनका साथ देगा या नहीं।

अधूरी केस डायरी पेश करने के आरोपी एसीपी को राहत

जयपुर, 5 सितंबर। जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 11 साल पहले दुष्कर्म के आरोपी की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के 164 के बयान केस डायरी में शामिल नहीं करने के आरोपी जवाजा, अजमेर के तत्कालीन एसएचओ व हाल में

- एसीपी पर दुष्कर्म के एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी की केस डायरी में पीड़िता के, धारा 164 के तहत दर्ज बयान को शामिल नहीं करने का आरोप था। अदालत ने एसीपी को आरोप मुक्त कर दिया है।

एसीपी पारसमल को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने 19 दिसंबर 2014 को लोक सेवक होते हुए जानबूझकर हाईकोर्ट के समक्ष अधूरी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नई जी.एस.टी. प्रणाली से राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई कब और कैसे होगी?'

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डैरेक ओ'ब्रायन ने सवाल उठाया

- ओ'ब्रायन ने यह भी चिन्ता जताई कि जी.एस.टी. से ज्यादा हानिकारक है, सरकार द्वारा लगाया ''सैस''। यह रकम 2012 में बजट का सात प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर, 2025 में बजट का बीस प्रतिशत हो गई है।
- ओ'ब्रायन के अनुसार ''सैस'' का सारा पैसा, केन्द्रीय सरकार के पास जाता है, इसमें से राज्य सरकार को एक पैसा भी नहीं मिलता।
- अतः केन्द्रीय सरकार को हो रही आमदनी का वो हिस्सा जो, राज्य सरकारों में बांटा जा रहा है, उसका स्कोप घटता जा रहा है।
- ओ'ब्रायन के अनुसार, सैस व सरचार्ज के तहत केन्द्रीय सरकार के पास 5.7 लाख करोड़ रुपया है।
- ओ'ब्रायन के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की टोटल रेवेन्यु का 89 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार में बंटता था, जो अब घटकर टोटल रेवेन्यु का केवल 79 प्रतिशत रह गया है।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 सितंबर। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने आज वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-जीएसटी) के लंबे समय बाद हुए सरलीकरण का स्वागत किया, लेकिन यह भी पूछा कि राज्यों को होने वाले टैक्स नुकसान की भरपाई कहां है?

ओ'ब्रायन ने बताया कि 2015 में जीएसटी बिल पर बनी संसद की प्रवर समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि कर की दर 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और टैक्स की विविधता से बचा जाना चाहिए।

अब ये हो गया। देर से ही सही, बेहतर है, ओ'ब्रायन ने लिखा, जो उस प्रवर समिति के सदस्य थे। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, ''चलो, अब यह हो गया। कमी नहीं से देर भली।''

बुधवार को जीएसटी काउंसिल ने दो-स्तरीय ढांचे की घोषणा की, जिसे केन्द्र सरकार एक बड़ा सुधार बताकर सराह रही है।

ओ'ब्रायन ने कहा कि अर्थशास्त्री अमित मित्रा, जो कभी ''एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फायनेंस मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी'' अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सलाहकार रहे हैं, ने भी जीएसटी के सरलीकरण का स्वागत किया पर शर्त रखी कि इसका लाभ आम जनता तक पहुंचे।

ओ'ब्रायन ने मित्रा के हवाले से लिखा, एक एंटी-प्रॉफिटियरिंग समिति थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। वह समिति अब नहीं रही है। दूसरा सवाल यह भी है कि राज्यों की भरपाई कैसे होगी। जीएसटी काउंसिल में 11 मंत्रियों ने भरपाई की मांग की थी, लेकिन उनकी आवाजें दबा दी गईं।''

ओ'ब्रायन ने लिखा कि राजस्व सचिव ने कहा कि 48000 करोड़ रु. की राजस्व हानि होगी। लेकिन उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को ध्यान में नहीं रखा। यह आसानी से एक लाख करोड रुपये से अधिक होगी।

तृणमूल के राज्यसभा नेता ने कहा कि जीएसटी को लेकर इतनी अधिक जितनी चर्चा हो रही है, लेकिन केन्द्र सरकार उपकर (सेस) के मुद्दे पर चुप है।

उन्होंने लिखा, जीएसटी की सारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुम्बई में बम धमाके करने की धमकी

मुंबई, 05 सितम्बर। मुंबई पुलिस को गुरुवार देर रात वॉट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला। इसमें दावा किया गया है कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं। आतंकी 400 किलो आरडीएक्स 34 गाड़ियों

- मुंबई पुलिस को वॉट्सऐप पर यह धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें कहा गया कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ गए हैं तथा 34 गाड़ियों में 400 किलो आर डी एक्स लगाकर ब्लॉस्ट करेंगे।

में लगाकर बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है।

धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने हाईअलर्ट घोषित कर दिया। क्राइम ब्रांच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर भारत-पाकिस्तान को ''क्लाईमेट चेंज'' के मामले में मजबूरन ''संयुक्त रणनीति'' बनानी पड़ेगी?

1960 में जब शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धाएं चरम पर थीं, भारत-पाक इण्डस वैली ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने के लिये विवश हुए थे

- अब यू.एन. (संयुक्त राष्ट्र संघ) ने तीन सौ अरब डॉलर का फंड स्थापित किया, जो विभिन्न देशों में वितरित किया जायेगा, ''क्लाइमेट चेंज'' के दुष्प्रभाव का सामना करने के लिये।
- पर, इस फंड का लाभ लेने के लिये, सभी राष्ट्रों को एन.डी.सी. (नेशनल डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन) पेश करने होंगे।
- भारत -पाक ने 2022 से एन.डी.सी. प्रस्तुत नहीं की है। रिपोर्ट पेश करने की डैड लाइन सितम्बर है।
- एक ''क्लाईमेट-चेंज'' विशेषज्ञ के अनुसार, धुंध व अन्य दुष्प्रभावों को, भारत -पाक के बीच आवागमन के लिये वाघा सीमा पर, पासपोर्ट की जरुरत नहीं होती।''
- आज जो तबाही मची है उत्तरी भारत में, उससे भी बदतर तबाही पाकिस्तान ने, 2022 में देखी थी, 33 मिलियन लोग बेघर हुए थे, तथा तीस अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था।
- क्या ''क्लाईमेट चेंज'' से निपटने के लिए ये मजबूरन यह ट्रीटी होगी?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 सितंबर। यदि किन्ही दो देशों को जलवायु परिवर्तन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए तो वे भारत और पाकिस्तान हैं। दोनों जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति पर स्थित हैं। वर्ष 2022 में, पाकिस्तान ने वह झेला जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ''जलवायु संहार (क्लाइमेट कार्नेज)'' कहा था - जब अभूतपूर्व बाढ़ से 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 30 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। भारत में भी हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने और बाढ़ आने से घर, स्कूल सड़कें तबाह हो रही हैं।

फिर आती है सर्दी। हर साल, उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्मॉग धुंध छा जाती है - दृश्यता शून्य हो जाती है, उड़ानें रद्द होती हैं, और करोड़ों लोग दमघोंटू हवा में जीते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह जहरीली हवा हर साल हजारों जिंदगियों को छोटा कर देती है। जैसा कि लाहौर के एक जलवायु कार्यकर्ता ने कहा, ''धुंध को वाघा पार करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हमारी साझा हवा ही हमारा साझा संकट है।''

1960 में, शीत युद्ध के तनावों के बीच, दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे एक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली को साझा किया गया था। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां आवश्यकता फिर से परस्पर सहयोग की मांग करे।

भीषण गर्मियों की आने वाली बाढ़ और सर्दियों में दमघोंटू धुंध के बावजूद ये दोनों पड़ौसी देश भारत और पाकिस्तान वर्ष 2022 और 2021 के बाद से अपनी जलवायु कार्रवाई योजनाओं को अपडेट नहीं कर पाए हैं, जबकि दांव पर अरबों डॉलर लगे हैं।

दक्षिण एशिया एक बार फिर जलवायु संकट की चपेट में है। इस समय, उत्तरी भारत में मूसलधार बारिश ने गांवों और खेतों को डुबो दिया है, पाकिस्तान में भी उफनती नदियां घरों और खेतों को बहा ले जा रही हैं।

पिछले साल बाकू में हुए सीओपी 29 सम्मेलन में, देशों ने जलवायु वित्त के लिए एक नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) पर सहमति जताई थी। इस समझौते के तहत विकासशील देशों के लिए हर साल 300 अरब डॉलर जुटाने का संकल्प किया गया है, जो 2035 तक बढ़कर 1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष हो जाएगा।

ये फंड देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने और बाढ़, सूखा व तूफानों जैसी आपदाओं से निपटने में मदद करने के लिए हैं। लेकिन इनका लाभ तभी मिलेगा जब देश अपने नैशनली डेटरमाइन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन (एनडीसी) को अपडेट करेंगे। बिना अपडेटेड योजनाओं के, ये पैसा मिलना असंभव है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक केवल 30 से कम देशों ने ही अपनी एनडीसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब के मु.मंत्री मान अस्पताल में भर्ती

पंजाब, 05 सितम्बर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत पिछले दो दिनों से खराब चल रही है और स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए

- भगवंत मान दो दिन से बुखार से पीड़ित हैं, तबियत में सुधार न होते देख डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी।

डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कर निगरानी और इलाज की सलाह दी है।

वहीं, इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने तय दौरे से पहले बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। सूत्रों के अनुसार, मान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)